भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1157
दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ

ई-पंचायत का विकास

1157. श्री प्रवीण पटेलः
श्री मनीष जायसवालः
श्री चावड़ा विनोद लखमशी:
श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री अनुराग शर्माः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मंत्रालय किस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए डिजिटल बुनियादी ढांचे और उपकरण सभी पंचायतों, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली पंचायतों के लिए सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल हों;

(ग) क्या ग्रामीण विकास और स्थानीय शासन पर इसके प्रभाव को और बढ़ाने के लिए ई-पंचायत एमएमपी हेतु भविष्य में कोई विकास योजना बनाई जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य : शासन और सर्विस डिलीवरी में उनकी दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाकर पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना, मैन्युअल त्रुटियों को कम करने के लिए नियोजन, बजट, लेखांकन, निगरानी और सामाजिक लेखापरीक्षा जैसे पंचायत कार्यों को स्वचालित करना, ग्रामीण नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायगी की सुविधा प्रदान करना और पंचायत अधिकारियों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाने के लिए डिजिटल उपकरण प्रदान करना है ।

विगत उपलब्धियों के आधार पर, पंचायती राज मंत्रालय ने ई-एमएमपी परियोजना के तहत, वर्ष 2020 में पंचायती राज संस्थाओं के लिए उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) सॉल्यूशन, ई-ग्रामस्वराज को लॉन्च किया था। यह एप्लिकेशन पंचायत के कामकाज के सभी पहलुओं जैसे नियोजन, बजट, लेखांकन, निगरानी, परिसंपत्ति प्रबंधन आदि को ऑनलाइन भुगतान सहित एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शामिल करता है। अब

तक, 2.54 लाख ग्राम पंचायतों ने 2024-25 के लिए अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) तैयार करके अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा, 2.41 लाख ग्राम पंचायतों ने 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के लिए ऑनलाइन लेनदेन पूरा कर लिया है। ई-ग्रामस्वराज को राज्यवार अपनाने की जानकारी **अनुबंध-I** में दी गई है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत ऑडिटऑनलाइन नामक एप्लीकेशन शुरू किया है। यह पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की अनुमति देता है और आंतरिक और बाहरी ऑडिट के बारे में विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड करता है। ऑडिट वर्ष 2022-23 के लिए, 2.58 लाख ऑडिट प्लान बनाए गए हैं और 2.57 लाख ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

मंत्रालय ने पंचायत प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए मेरी पंचायत और पंचायत निर्णय जैसे ऐप भी शुरू किए हैं। जहां मेरी पंचायत योजना, गतिविधियों और कार्य प्रगति की जानकारी जनता के लिए सुलभ बनाती है, वहीं पंचायत निर्णय ग्राम सभा की कार्यवाही में पारदर्शिता और प्रबंधन को बढ़ाता है।

(ख) पंचायती राज मंत्रालय ने ई-पंचायत एमएमपी के तहत डिजिटल समावेशिता और पहुंच में आसानी सुनिश्चित करने हेतु कई उपाय किए हैं, जिनमें ई-ग्रामस्वराज और ऑडिटऑनलाइन जैसे उपयोगकर्ता-अनुकूल (यूजर फ्रेंडली) सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का विकास, भाषिणी के साथ एकीकरण करके इन ऑनलाइन अनुप्रयोगों के लिए बहुभाषी समर्थन प्रदान करना और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने पर पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल है।

इसके अलावा, दूरदराज के क्षेत्रों में पंचायतों को डिजिटल सेवाओं की प्रदयगी करने हेतु , संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत, उनकी वार्षिक कार्य योजनाओं में प्रस्ताव के आधार पर, मंत्रालय कंप्यूटरों की खरीद के लिए सीमित पैमाने पर सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ के प्रयासों में सहायता कर रहा है।

(ग) & (घ) मंत्रालय ई-एमएमपी परियोजना के परिणामों में सुधार लाने और जमीनी स्तर पर बेहतर प्रशासन हेतु नियमित रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ रहा है इसके अतिरिक्त मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर मौजूदा एप्लीकेशन जैसे ई-ग्रामस्वराज, प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल आदि में आवश्यक सुधार और संवर्द्धन किए जा रहे हैं, साथ ही समर्थ एप्लिकेशन, मेरी पंचायत ऐप, पंचायत निर्णय ऐप आदि जैसे नए एप्लीकेशन तैयार किए गए हैं।

***

अनुबंध-I

'ई-पंचायत का विकास' के संबंध में दिनांक 11.02.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1157 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज को अपनाना

क. सं	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों एवं समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों की कुल संख्या	ऑनबोर्ड जिला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें
1	आंध्र प्रदेश	13328	13296	12907	660	660	639	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2106	185	0	0	0	25	25	7
3	असम	2662	2197	2170	191	191	185	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8044	534	534	529	38	38	38
5	छत्तीसगढ़	11596	11594	11503	146	146	146	27	27	27
6	गोवा	191	191	89	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14656	14594	13666	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6225	6221	5829	143	143	131	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3614	3509	81	81	80	12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4317	264	264	262	24	24	23
11	कर्नाटक	5954	5954	5935	238	232	117	31	31	28
12	केरल	941	941	940	152	152	152	14	14	14
13	मध्य प्रदेश	23011	23009	22973	313	313	310	52	52	52
14	महाराष्ट्र	27911	27834	26268	351	351	302	34	34	34
15	मणिपुर	3180	161	120	0	0	0	12	6	4
16	मेघालय	6817	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	842	842	832	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	1289	186	0	0	0	0	0	0	0

क. सं	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों एवं समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों की कुल संख्या	ऑनबोर्ड जिला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें
19	ओडिशा	6794	6794	6792	314	314	314	30	30	30
20	पंजाब	13237	13222	9173	152	151	110	22	22	19
21	राजस्थान	11211	11206	10739	361	353	351	33	33	33
22	सिक्किम	199	199	194	0	0	0	6	6	6
23	तमिलनाडु	12525	12525	12518	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12771	12768	12628	540	540	498	32	32	32
25	त्रिपुरा	1194	1176	1162	75	75	75	9	9	8
26	उत्तराखंड	7795	7794	7729	95	95	95	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57691	57691	57596	826	826	821	75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3338	345	345	345	22	21	21
कुल संख्या		**263481**	**251853**	**241156**	**8658**	**6402**	**6098**	**650**	**62**	**609**